श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : सर, वह तो जो वहां की मैंनेजमेंट है वह सफाई का ध्यान रखती है। हम तो लोगों को वहां पहुंचाने का काम करेंगे ।....(व्यवधान)...

श्री एस0एस0 अहलुवालिया: सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि दसम् गुरु गोविन्द सिंह जी महाराज की तपो भूमि हेमकुंड साहिब भी बदरीनाथ के नजदीक वैली ऑफ प्लावर्स के सथ पड़ती है जहां कि लाखों की संख्या में लोग जाते हैं। तो क्या यह हैलीकॉप्टर सेवा आप हेमकुंड साहिब के लिए भी शुरु करेंगे?

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : सभापति महोदय, मैं बिहार का हूं और गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म स्थान पटना साहिब है, इसलिए मैं उनका बहुत ही आदर करता हूं। मैं यह मानता हूं कि यह हम हैलीकॉप्टर की पहली सेवा केदारनाथ के लिए शुरु कर रहे हैं और अगर यह सफल हुई तो इस तरह की सेवा और जगह भी शुरु करेंगे।

श्री सभापति : प्रश्न संख्या 635।

नदियों को जोड़ने के लिए विश्व बैंक से ऋण

*635 **श्री रमा शंकर कौशिक:** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार नदियों को जोड़ने के लिए विश्व बैंक से ऋण ले रही है;

(ख) यदि हां, तो ऋण की राशि कितनी है और क्या सरकार ने इस ऋण को लेने के लिए कोई जल नीति बनाई है;

(ग) यदि हां, तो नीति का ब्यौरा क्या है;

(घ) देश में वर्तमान में पानी की उपलब्धता क्या है;

(ड़) क्या सरकार विदेशी दवाब में नदियों को बेचने जा रही है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो 16 मार्च के राष्ट्रीय सहारा में प्रकाशित समाचार पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है।

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन चरण सेठी): (क) से (छ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क)से (ग) नदियों को जोड़ने के लिए सरकार द्वारा विश्व बैंक से ऋण लिए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। अत: ऋण लेने के लिए राशि और नीति का प्रश्न नहीं उठता।

(घ) देश में औसतन 4000 बिलियन घनमीटर (बीसीएम) वार्षिक वर्षा (हिमपात सहित) होती है । इसमें से देश की नदी प्रणालियों में औसत वार्षिक प्रवाह 1869 बिलियन घन मीटर है । उपयोग योग्य सतही जल के 690 बिलियन और वार्षिक पुनर्भरणीय भूजल संसाधनों के 432 बिलियन घनमीटर होने का अनुमान लगाया गया है ।

(ड़) और (च) जी, नहीं। हमारी नदियों को बेचे जाने की कोई संभावना नहीं है ।

(छ) 16 मार्च, 2003 के 'राष्ट्रीय सहारा' में छापे समाचार से देश में जल संसाधनों की उपलब्धता और नीतिगत पहलुओं की वास्तविक स्थिति का पता नहीं चलता है । समय-समय पर उपयोग किए जाने वाले जल संसाधनों आंकड़े नवीनतम आंकड़े होते हैं । देश की नदियों के निजीकरण के लिए कोई प्रस्ताव न तो भारत सरकार के विचाराधीन है और न ही ऐसा करने का विचार है। राष्ट्रीय जल नीति में अन्य बातों के साथ-साथ जहां कहीं संभव हो वहां विभिन्न उपयोगों के लिए जल संसाधन परियोजनाओं की आयोजना, विकास और प्रबन्धन में निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए व्यवस्था है। जल संसाधन सुविधाएं मुहैया कराने के लिए विशेष स्थितियों के आधार पर निजी क्षेत्र की भागीदारी के विभिन्न संयोजनों पर विचार किया जा सकता है ।

World Bank loan for river linking

†*635. SHRI RAMA SHANKER KAUSHIK: Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) whether loan is being taken by Government from the World Bank for linking the river;

(b) if so, the amount of loan and whether Government have formulated any water policy for getting the loan;

(c) if so, the details of the policy;

(d) the present availability of water in the country;

(e) whether Government are going to sell our rivers owing to external pressures;

(f) if so, the details of the same; and

(g) if not, the reaction of Government to the news item published in the Rashtriya Sahara on 16th March ?

†Original notice of the question was received in Hindi.

THE MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI ARJUN CHARAN SETHI): (a) to (g) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (c) There is no proposal for taking loan by the Government from the World Bank for linking of rivers. As such the amount and policy for loan does not arise.

(d) There is an average annual precipitation (including snowfall) of 4000 Billion Cubic Meter (BCM) in the country. Out of this, the annual average flow in the river systems of the country is 1869 BCM. The utilizable surface water is assessed as 690 BCM and the annual replenishable ground water resources is 432 BCM.

(e) and (f) No, Sir. There is no possibility of selling our rivers.

(g) The news-item published in the 'Rashtriya Sahara' on 16th March, 2003 does not reflect the factual position about the water resources availability in the country and policy aspects. The data on water resources used from time to time are the current data. There is no proposal under consideration or contemplated by the Government of India for privatization of rivers in the country. The National Water Policy *inter-alia* provides for private sector participation in planning, development and management of water resources projects for diverse uses wherever feasible. Depending upon specific situation, various combination of private sector participation for providing water resources facilities may be considered.

श्री रमा शंकर कौशिक : श्रीमन् माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में वर्षा से मिलने वाले जल की और भू-जल की मात्रा दी है, लेकिन माननीय मंत्री जी जानते हैं कि इस समय हमारे देश में हजारों ब्लॉक डार्क घोषित हो चुके हैं और वे सरकार ने ही किए हैं। महोदय, स्थिति ऐसी है कि ट्यूबवेल लगाने के लिए पंखे 20 -20 मीटर, 30 -30 मीटर नीचे रखने पड़ते हैं तब जाकर पानी ऊपर आता है। ऐसी स्थिति में माननीय मंत्री जी ने जो ने जो आंकड़े दिए हैं, मैं जानना चाहता हूं कि वे आंकड़े कौन से वर्ष के हैं जबकि उन्होंने इन्हें नवीनतम बताया है जबकि मुझे तो ये 40 साल पुराने लगते हैं?

SETHI: Sir, the figures given by me are related to the year 2000 and are not 40 years old. They are up-to-date figures. So far as dark blocks are concerned, the question is something else. The hon. Member is asking about ground water, but the question is whether the World Bank funding

is being sought by the Government for linking the rivers. So, the question is something else. But if you permit me, I can answer the question. The question is not related to ground water.

श्री रमा शंकर कौशिक : श्रीमन् माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है, उसे देख लें। मंत्री जी ने स्वयं इस वाटर की उपलब्धता बताई है । उन्होंने अपने उत्तर में बताया है कि हमें इतना पानी बारिश से मिलता है , इतना हिमपात से मिलता है, इतना सतह से मिलता है और इतना भू-जल मिलता है ....(व्यवधान)...

श्री सभापति : आपने क्वैश्चन पूछा है कि देश में वर्तमान में पानी की उपलब्धता क्या है? यह नदियों के पानी से संबंधित है या ग्राउंड वाटर से संबंधित है?

श्री रमा शंकर कौशिकः श्रीमन् सबसे है ।

श्री सभापति : क्वैश्चन तो नदियों का चल रहा है।

श्री रमा शंकर कौशिक : श्रीमन् पानी की उपलब्धता का मतलब तो वर्षा भी है, हिमपात भी है, सतही जल भी है और भू-जल भी है ।...(व्यवधान)...

SHRI ARJUN CHARAN SETHI: Sir, it is a fact that depletion of ground water has taken place in many parts of the country. My Ministry has not only written to different States about this, but a model Bill has also been circulated in this regard. If that model Bill is enacted, the extraction of ground water can be regularised and the ground water can be made richer by taking various measures. But, unfortunately, that model Bill has not been enacted by many of the States. Only two or three State Governments have enacted it. So, we are persuading and requesting the State Governments, time and again, so that this Bill can be enacted. If it is implemented, extraction of ground water can be regulated and regularised.

श्री रमा शंकर कौशिक : श्रीमन् मेरा दूसरा पूरक प्रश्न यह है कि माननीय मंत्री जी ने कहा है कि हम नदियों को जोड़ने की योजना बना रहे हैं और उसके लिए हम विदेश से कोई ऋण नहीं ले रहे हैं। मेरे पूरक प्रश्न का भाग-1 यह है कि अगर आप कहीं से ऋण नहीं ले रहे हैं तो कृपया बताएं कि 5 लाख 60 हजार करोड़ रुपए के खर्चे का जो आंकलन किया गया है, उसकी आपूर्ति आप कहां से करेंगे और नंबर -2 माननीय मंत्री जी ने कहा है कि नदियों के निजीकरण और बेचने की स्थिति में नहीं है, लेकिन जल नीति में माननीय मंत्री जी ने जल को संपत्ति घोषित किया है । उन्होंने स्वयं कहा है कि राष्ट्रीय जल नीति में अन्य बातों के साथ-साथ जहां कहीं संभव हो वहां विभिन्न उपयोगों के लिए जल- संसाधन परियोजनाओं की आयोजना, विकास और प्रबंधन में निजी क्षेत्र की भागीदारी की व्यवस्था है । इस निजीकरण कि व्यवस्था में क्या स्थिति बनेगी, किस प्रकार

से वे पानी को सप्लाई करेंगे, किस प्रकार से वे पैसा अपना लेंगे, कैसे वापस करेंगे? उसमें स्थिति वही आ जाती है, जो मैंने प्रश्न किया है। तो माननीय मंत्री जी इसका खुलासा करें।

SHRIARJUN CHARAN SETHI: Sir, as far as the question of funding is concerned, the Task Force has been set up by the Government, and various aspects of this particular project are being studied. Whenever the Task Force makes its report available to the Government, it will certainly give suggestions about the funding aspect, as well as various other modalities. It will certainly do so, and it will become known to the Government, and I can certainly report back to the House.

So far as the question of private participation is concerned, since the hon. Member has referred to this question, I would like to quote para 13 of the National Water Policy. I quote. "This is not privatisation at all. Wherever there is possibility, we can take the help of the private parties for supplementing the efforts of the Government. But, this is not privatisation."

श्री लालू प्रसाद: महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं। नदियों को जोड़ने के सवाल को लेकर अपने देश में एक बहुत खतरनाक स्थिति पैदा की जा रही है। भले ही इसको चाहे ये लोग हल्का-फुल्का लें, मगर आज भी अपने मुल्क में कर्नाटक और तमिलनाडु के पानी का विवाद सुप्रीम कोर्ट से लेकर चारों तरफ एक विवाद का कारण बना हुआ है। महोदय, नदियों को जोड़ने के नाम पर गारलैंड स्कीम और महामहिम राष्ट्रपति जी के भाषण में भी इसका जिक्र किया ग्या है और मैं जो संकेत देख रहा हूं, जिम्मेदारी के साथ मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना भी चाहता हूं, पूछना भी चाहता हूं और बताना भी चाहता हूं कि राज्य-राज्य निकट भविष्य में लड़ने वाले हैं, संघर्ष करने वाले हैं क्योंकि अपने हक को कोई भी आदमी या कोई भी पार्टी छोड़ने वाली नहीं है। हमने जो समझा है, माननीय मंत्री जी के यहां एक्सपर्ट लोग या जो लोग यह बात चला रहे हैं उनकी अपनी समझ कुछ हो सकती है।...(व्यवधान).. महोदय, यह बड़ा गंभीर मामला है।

श्री सभापतिः ठीक है, लेकिन क्वैश्चन तो नहीं हुआ।

श्री लालू प्रसाद : महोदय, अपने देश में कहा पानी है, वह सबको पता है। बिहार में पानी है, उत्तर प्रदेश से होकर जो गंगा आती है, उसमें तमाम पानी है।

श्री सभापति : लालू जी, अभी और इम्पोर्टेंट क्वैश्चन आने वाले हैं।

श्री लालू प्रसाद : मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं। महोदय, एक तो पीआईएल हुआ था सुप्रीम कोर्ट में और यह पानी, नदी स्टेट सब्जेक्ट है, आपको यह समझना चाहिए। यह

टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन राज्यों का है और विद आउट कन्सेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट आपने यह पढ़वा दिया महामहिम राष्ट्रपति जी से। हमने सुना है कि हमारा पानी, बिहार का पानी और ब्रह्मपुत्र का पानी आप उल्टी ओर चलाना चाहते हैं, कावेरी बेसिन में ले जाना चाहते हैं। हर राज्य आपसे यह जानना चाहेगा क्योंकि उसका हक है हर राज्य का, कि हमारे यहां पानी कम होगा तो यह पानी कहां से उठाएंगे? फिर पोल्यूशन से हजारों गांव प्रभावित होंगे।

श्री सभापतिः लालू जी, यह बात आप अलग से उठाइए।

श्री लालू प्रसादः महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि इस तरह का जो आपका इरादा है राज्य-राज्य को लड़ाने का, इस इरादे से आप अपने को अलग कर लीजिए क्योंकि पानी, नदी स्टेट सब्जेक्ट है और कहीं भी कोई राज्य अपने यहां सूखा कर दूसरे को पानी नहीं देगा। इसमें जो कितने लाखों, हजारों करोड़ रुपया लगेगा, वह कहां से आएगा? बताइए। हम तो अपना पानी कहीं नहीं जाने देंगे।

श्री सभापतिः मंत्री जी, इसका जवाब देने से काम नहीं चलेगा। यह तो एक जनरल बात इन्होंने कही है। इसका आप ध्यान रखिए।

श्री लालू प्रसाद : महोदय, इस पर एक दिन डिसकशन करवा दीजिए। यह एक भयानक बात होने वाली है, मार-काट होने वाली है।

श्री सभापतिः मैं वही कह रहा हूं अलग से बात हो। आप बिजनेस एडवायजरी कमेटी में यह मामला रखें ।I Question No. 636. *(Interruptions)*

Projected loss of IA

*636. SHRIMATIBIMB A RAIKAR: Will the Minister of CIVIL AVIATION be pleased to state :

whether despite cut in Aviation Turbine Fuel costs, Indian Airlines is likely to incur a loss for the year 2002-2003;

whether IA propose to pull out from non-trunk routes to save more than Rs. 200 crores;

whether IA has sold off its real estate holdings in Delhi and Chennai in an attempt to balance the books; and

if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF CIVIL AVIATION (SHRI SYED SHAHNAWAZ HUSSAIN): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.